

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम भेजी) हाथरस

आ. संख्या- 33

अन्तर्गत धारा-143 जाविदो

गौजा-कलेक्टर हाथरस।

डॉ० वी०पी० सिंह मटनावात

बनाम

सरकार

निर्णय

उक्त वाद की कार्यवाही डॉ० वी०पी० सिंह मटनावात पुत्र श्री युधिष्ठिर सिंह, निवासी मगता आल हाथरस जिला हाथरस द्वारा जाविदो और भूव्यवहारी अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.02.13 पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थी का नाम भूमि स्थित ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474 हे० लगानी 20.55 रुपये भूमि का सांख्यिकीय भूमिधर दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग के रूप में उपयोग में न लाई जाकर अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तत्कम में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल से जांच कराई गई। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 13.02.2013 में "ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474 हे० लगानी 20.55 रुपये पर कृषि प्रयोग में नही लाये जाने के कारण इस अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संतुष्टि की है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयानों में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोग में नही लाई जा रही है। अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में इस भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थी का है, जो नियमों के विपरीत नही है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार ट्रान्सफर हुई है। यह भूमि कमी भी धारा 132, नजूल, वन विभाग, ग्रामसभा, नगरपालिका की नही रही है और इस भूमि पर मत्स्य एवं कुक्कुट पालन आदि नही हो रहा है। प्राप्त आख्या के आधार पर वाद घोषित किया गया।

राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 8164/5-49ए/03 दिनांक 28.01.04 में व्यवस्था है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वधरेषणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। पशुगत भूमि का उपयोग गैर कृषि उपयोग में किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपव्ययन हो रही है। राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-5 लखनऊ के पत्रांक 8410/जी-5-22ए/07 दिनांक 02.08.2007 में उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० जाविदो एवं भूमि व्यवहारी अधिनियम 1950 की धारा 145 में प्रावधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब-रजिस्ट्रार को भेजी जाये, जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुये भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबंधित कर लेगा। प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपव्ययन रोका जाये। अतः शासनादेशों के अनुपालन में इस भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व परिषद अनुभाग-5 के पत्रांक 16697/5-28ए/08 दिनांक 22.06.10 में उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच करने पश्चात्, जो नियत की जाये, उस का प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० जाविदो एवं भूव्यवहारी अधिनियम 1952 के नियम 135 एवं 136 में धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है। परिषद द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि शहरी क्षेत्रों की आबादी के आस-पास की



7m

कृषि भूमि जो सामान्यतया अर्द्धकृषि हो जाती है, के वास्तविक प्र. उपयोग का इन्तजान न होने के कारण विक्रय अभिलेखों में उसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर कम मूल्यांकन करके करापवचन किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये उ०प्र० ज०वि० और भू०व्य० अधि० 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि धारा 143 के प्रव्यापन तथा उ०प्र० ज०वि० एवं भू०व्य० अधि० 1952 के नियम 135 व 136 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत जो भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाई जा रही है, प्रख्यापन कर उसको अभिलेखों में दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या एवं शासनादेशों के क्रम में भांजा ग्राम कौलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474 है० लगानी 2055 रुपये को रटाम्प अपवचना रोकने के उद्देश्य से कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु अर्द्धकृषि भूमि घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित होने पर धारा-143 का प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रयोज्य होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार हाथरस को अभिलेखों में अंकित करने हेतु भेजी जाये तथा एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक हाथरस को उ०प्र० ज०वि० अ० एवं भू०व्य० अधि० की धारा 143 संपठित नियम 137 में अपेक्षानुरूप इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यद्यपि निबन्धित(दैनिक रजिस्टर) में कर, अपने हस्ताक्षर सहित न्यायालय में लौटा के। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त दाखिल दफ्तर की जाये।



(Handwritten Signature)
 उपजिलाधिकारी,
 हाथरस।

21-2-2013
 23-2-2013
 23-2-2013
 7502

प्रमाणित प्रतिलिपि
(Signature)
 सबना अधिकारी/मजिस्ट्र
 हाथरस

PEE

PEE

PEE



बाद संख्या-

42

न्यायालय उप जिलाधिकारी, हाथरस।

अध्याय-143 जांचित एवं भूव्यवस्थापन
मौजा-कैलोरा तहसील-हाथरस।

बाग पीठपोरिह मदनवात

बंगला

सरकार

नकल आदेश

उक्त बाग की कार्यवाही बाग पीठपोरिह मदनवात कालवा बाग एजुकेशनल एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में कैलोरा तहसील द्वारा संस्थापक डॉ पीठपोरिह मदनवात पूर्व यूपिटर रिज मदनवात जिलाधी नगला आल तहसील हाथरस के कालवा बाग पर प्रारम्भ हुई। अंततः वर्षी बाग पीठपोरिह मदनवात कालवा बाग एजुकेशनल एण्ड प्रशासनिक क्षेत्रों में कालवा तहसील द्वारा संस्थापक डॉ पीठपोरिह मदनवात पूर्व यूपिटर रिज मदनवात जिलाधी नगला आल तहसील हाथरस की भूमि स्थित बाग कालवा के खाता संख्या 111 गाटा संख्या 532 रकबा 0.47380 लगानी 20.55 रुपये के सकलभूमि भूमि है तथा उक्त भूमि में एक मकान बनाये हुये है तथा बाग और वाउण्ट्री वाल कर्ने हुयी है, जिनमें आबादी के प्रकार में जाना चाहते है। भूमि को आबादी घोषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

तलहम में उक्त की जांच तहसीलदार हाथरस से करायी गयी। तहसीलदार हाथरस द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपनी जांच अख्त दिनांक 24.12.09 द्वारा उपलब्ध करायी हुये अदमत कराया गया है कि बाग कैलोरा के खाता संख्या 111 गाटा संख्या 532 रकबा 0.47380 लगानी 20.55 रुपये में कृषि कार्य नहीं कर रहे है। वर्तमान में उक्त रकबा में एक मकान व घास और वाउण्ट्री वाल बनी हुयी है, आबादी घोषित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति की है। हल्का लेखपाल के ब्यान अभिलिखित कराया गया है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने ब्यान में कहा है कि उक्त भूमि कृषि कार्य में नहीं आ रहा है, भूमि रिकार्डों के परिपेक्ष्य में भूमि का स्कांमि- एवं कृषि प्राधिकरणों का है, निरणी के विषय में नहीं है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार प्रारम्भ हुई है तथा कर्ने भी घास 132, नजूल, जन विभाग, बाग रकम/अदमत पारितवा की जांच की जा आबादी घोषित किये जाने हेतु अभिलिखित कराया।

अतः तहसीलदार हाथरस की संस्तुति के आधार पर प्रश्नगत भूमि स्थित बाग कालवा के गाटा संख्या 532 रकबा 0.47380 लगानी 20.55 रुपये भूमि को कृषि भूमि से निम्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निर्बंधक हाथरस को उ0प्र0 जमींदारी विभाग अधिनियम की धारा 145 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा एक प्रति तहसीलदार हाथरस को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु भेजी जाये। बाग आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दफ्तिल दफतर हं।

दिनांक -

5/5/10
8-6-2010
8-6-2010
150 रु
2

sd-
उप जिलाधिकारी,
हाथरस।

स्वागत : किलिनि
R.V.
8/5/10



न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (ग्राम भेणी) हाथरस

घाट संख्या- 33

अन्तर्गत घाट-143 ज०वि०.८०

मौजा-कैलोरा तहसील-हाथरस।

का० वी०पी० सिंह मदनगढ

बनाम

सरकार

नूतन निर्णय

उक्त घाट की कार्यवाही का वी०पी० सिंह मदनगढ पुत्र श्री युक्तिर सिंह, निवासी नगला आल तहसील सिकन्दाराऊ जिला हाथरस द्वारा ज०वि० और भू०व्य० अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.13 पर धारणा हुई। प्राची का नाम भूमि स्थित ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474 हे० लगानी 2055 रूपये भूमि का संकलनीय भूमिधर दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग के रूप में उपयोग में न लाई जाकर अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

तत्कम में प्राची के प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल से जांच कराई गई। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 13.02.2013 में "ग्राम कैलोरा के खाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474 हे० लगानी 2055 रूपये पर कृषि प्रयोग में नहीं लाये जाने के कारण इसे अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की सलाह की है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयानों में उल्लेख किया है कि उक्त भूमि कृषि प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। अभिलेखों के परिप्रेष्य में इस भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्राची का है, जो नियमों के विपरीत नहीं है। सम्बन्धित भूमि नियमानुसार ट्रान्स्फर हुई है। यह भूमि कभी भी धारा 132, नजूल, वन विभाग, ग्रामसभा, नगरपालिका की नहीं रही है और इस भूमि पर मत्स्य एवं कुक्कुट पालन आदि नहीं हो रहा है। प्राप्त आख्या के आभार पर घाट खोजित किया गया।



राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-5 तखनऊ के पत्रांक 8164/5-49ए/03 दिनांक 28.01.04 में व्यवस्था है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर उप-जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वघरेणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत भूमि का उपयोग गैर कृषि उपयोग में किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवचन हो रही है। राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग-5 तखनऊ के पत्रांक 6416/जी-5-22ए/07 दिनांक 02.08.2007 में उल्लेख है कि संकलनीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असाब्द प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० ज०वि० एवं भूमि व्य० अधि० 1950 की धारा 145 में प्राविधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब-रजिस्ट्रार को भेजी जाये, जिससे वह इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुये भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से-निबन्धित कर लेगा। प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवचन रोका जाये। अतः शासनादेशों के अनुपालन में इस भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व परिषद अनुभाग-5 के पत्रांक 10697/5-28ए/08 दिनांक 22.08.10 में उल्लेख है कि संकलनीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असाब्द प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगना के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जांच करने परवात, जो नियत की जाये, उस का प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० ज०वि० एवं भू०व्य० अधि० 1952 के नियम 135 एवं 136 में धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने की विस्तृत प्रक्रिया दी गयी है। परिषद द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि शहरी क्षेत्रों की आबादी के आस-पास की

(Handwritten signature)

कृषि भूमि जो सामान्यतया अकृषिक हो जाती है के वारसिक भू उपयोग का इन्दाज में होने के कारण विक्रय अभिलेखों में उसे कृषि भूमि के रूप में दर्शाकर कम मूल्यांकन करके करावधान किया जा रहा है। इस प्रकृति को रोकने के लिये 30प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन तथा 30प्र0 ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 1952 के नियम 135 व 136 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत जो भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाई जा रही है, प्रख्यापन कर उसको अभिलेखों में दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या एवं शासनादेशों के क्रम में मौजा ग्राम कौलोरा के छाता संख्या 100 गाटा संख्या 533 रकबा 0.474है0 लगानी 20.55 रुपये को स्टाम्प अपवधाना रोकने के उद्देश्य से कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि प्रसंगत भूमि के क्रय धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित होने पर धारा-143 का प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रयोज्य होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार हाथरस को अभिलेखों में अंकित करने हेतु भेजी जाये तथा एक प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक हाथरस को 30प्र0 ज0वि0 30 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 संपठित नियम 137 में अपेक्षानुरूप इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथावत निबन्धित(दैनिक रजिस्टर) में कर, अपने हस्ताक्षर सहित न्यायालय में लौटा दें। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक:-

Handwritten signature
उपजिलाधिकारी,
हाथरस।



Handwritten signature
उपनिबन्धक
हाथरस

18-2-2013
21-2-2013
21-2-2013
450 रु०
Handwritten signature



Handwritten mark